वी. एस. अग्रवाल, न्यायमूर्ति, के समक्ष

महर्षि दयानंद शिक्षा समाज & अन्य,-याचिकाकर्ता
बनाम

सत्येंद्र भादन और अन्य,-उत्तरदाता

सी. आर. सं. 2849 सन *1998*

17 नवंबर, 1998

सिविल प्रक्रिया संहिता, *1908*-धारा *92,* आदेश *1* आर. एल. *8*-ऑर्डर *1* आर. एल. का दायरा। *8*-प्रतिनिधि मुकदमा दायर करने के लिए न्यायालय की अनुमति-प्रारंभिक चरण में कोई अनुमति प्राप्त या प्रदान नहीं की गई -

मुक़दमे की अनुरक्षण-मुक़दमे के लंबित रहने के दौरान दी गई ऐसी अनुमति-क्या वैध है।

*(*ठाकुरदवारा, पटियाला और अन्य बनाम नगर सिंह और अन्य, *1998 (3)* पी. एल. आर. *81* और पृथ्वीपाल सिंह बनाम माघ सिंह और अन्य, ए. आई. आर. *1982* पी. एंड एच*., 137,* विशिष्ट*)*

अभिनिर्धारित किया कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 8 के प्रावधान अनिवार्य हैं।

आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि बारीकी से जांच करने पर, संहिता की धारा 92 और फिर यह कहा गया कि, आदेश 1 नियम 8 के तहत प्रावधानों के बीच एक स्पष्ट अंतर निकाला जाता है।संहिता की धारा 92 के तहत, सूक्ष्म आकलन से, इन शब्दों का उपयोग करता है "और न्यायालय की अनुमति प्राप्त करने के बाद एक मुकदमा दायर कर सकता है।"यह स्पष्ट है कि यह मुकदमे के दायर करने से पहले एक अनिवार्य शर्त है।इस तरह की अनुमति के बिना मुकदमा आगे नहीं बढ़ सकता है।जबकि संहिता के आदेश 1 नियम 8 के तहत, विधानमंडल ने "न्यायालय की अनुमति से" अभिव्यक्ति का उपयोग किया है।यद्यपि मुकदमा दायर करने से पहले न्यायालय की अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए, फिर भी इसे स्थगित किया जा सकता है और बाद में मुकदमा लंबित रहने के दौरान दिया जा सकता है।भाषा में स्पष्ट अंतर है।संहिता की धारा 92 के तहत, कोई भी कदम उठाने से पहले अदालत की आवश्यक अनुमति आवश्यक है।संहिता के आदेश 1 नियम 8 के तहत दायर मुकदमे में ऐसा नहीं होगा।

(पैरा 18)

याचिकाकर्ता की ओर से ए. पी. एस. अहलूवालिया, अधिवक्ता, जे. एस. भट्टी, अधिवक्ता और हेमंत मल्होत्रा, अधिवक्ता।

आर. एस. सिहोटा, अधिवक्ता, प्रत्यर्थी की ओर से।

निर्णय

वी. एस. अग्रवाल, न्यायमूर्ति

वर्तमान पुनरीक्षण याचिका को महर्षि दयानंद एजुकेशन सोसाइटी, फरीदाबाद और अन्य लोगों द्वारा दायर किया गया है जिन्हें इसके बाद "याचिकाकर्ता" के रूप में वर्णित किया गया है।यह विद्वत

विचारण न्यायालय और विद्वत अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, फरीदाबाद के क्रमशः 11 फरवरी, 1994 और 5 जून, 1998 के आदेश के खिलाफ निर्देशित किया गया है।विद्वत विचारण न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 1 और 2 के तहत प्रतिवादीगण द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया था।उक्त आदेश को फरीदाबाद के विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने बरकरार रखा।

(1) प्रासंगिक तथ्य यह है कि प्रतिवादी सत्येंद्र भडाना और अन्य लोगों ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक दीवानी मुकदमा दायर किया था।यह आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता-सोसायटी एक पंजीकृत शैक्षिक संस्था है जो महर्षि दयानंद की शिक्षाओं के प्रचार और शिक्षा के उद्देश्य को बढ़ावा देने में लगी हुई है।यह फरीदाबाद क्षेत्र में विभिन्न शैक्षणिक संस्थान, स्कूल और कॉलेज चला रहा है।याचिकाकर्ता-सोसायटी के प्रबंधक निकाय में 15 सदस्य होते हैं।चार को पदाधिकारी कहा जाता है और अन्य सदस्य (गैर-आधिकारिक सदस्य) होते हैं।चुनाव हर तीन साल में होना था और सामान्य निकाय के सदस्य ही प्रबंधक निकाय के सदस्यों का चुनाव करने के पात्र होते हैं।अध्यक्ष और प्रबंधक निकाय निकाय का कार्यकाल समाप्त हो गया था और केवल चार अनिवार्य सीटों, अर्थात् अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और खजांची के चुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम को अधिसूचित करते हुए एक सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी।वादी-प्रत्यर्थियों ने दावा किया कि वे याचिकाकर्ता संख्या 1 के सामान्य निकाय के प्रामाणिक सदस्य हैं।उन्होंने अब तक अपनी सदस्यता का भुगतान कर दिया था। प्रबंधक निकाय के सदस्यों को याचिकाकर्ता-समाज के मामलों का कुप्रबंधन करने के लिए कहा गया था और उनकी गतिविधियाँ पूर्वाग्रहपूर्ण और न्याय के हित के लिए हानिकारक थीं।वे नापाक गतिविधियों में लिप्त थे और समाज को आर्थिक नुकसान पहुँचा रहे थे।वे याचिकाकर्ता-सोसायटी के मामलों के प्रबंधन पर नियंत्रण रखना चाहते थे और इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने सामान्य निकाय के सदस्यता रिकॉर्ड को गढ़ा और सदस्यों की सूची में लगभग सत्तर व्यक्तियों के नाम जोड़े।वे 70 सदस्य याचिकाकर्ता-समिति के विधिवत नामांकित सदस्य नहीं थे और न ही उन्होंने अपनी सदस्यता का भुगतान किया है।यदि झूठे सदस्यों को अपना वोट डालने की अनुमति दी जाती है, तो चुनाव का परिणाम भौतिक रूप से प्रभावित होने की संभावना है।अतः इस प्रकार अधिसूचित चुनाव कार्यक्रम को इस आधार पर अवैध कहा गया कि सोसायटी के सचिव द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना अत्यधिक अवैध है क्योंकि सोसाइटी के सचिव का कोई पद नहीं है; चुनाव कार्यक्रम अवैधता से दूषित है क्योंकि इसमें प्रबंधक निकाय के अन्य ग्यारह गैर-सरकारी सदस्यों के चुनाव के समय, तिथि और तरीके का खुलासा नहीं किया गया है, चुनाव अधिकारी/निर्वाचन अधिकारी के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है और सके, केवल चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने के लिए झूठे नाम शामिल किए गए हैं। प्रतिवादीगणओं संख्या 2 से 4 को संस्थापक सदस्यों के रूप में दिखाया गया है, लेकिन वास्तव में, वे ऐसे नहीं हैं।मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, प्रतिवादी-याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी-याचिकाकर्ताओं को चुनाव कराने से रोकने के लिए अंतरिम निषेधाज्ञा का अनुरोध किया।

(2) दायर किए गए लिखित बयान में, दीवानी मुकदमा भी विज्ञापन अंतरिम निषेधाज्ञा की मांग करने वाले आवेदन को चुनौती दी गई थी।यह दावा किया गया कि प्रतिवादी-वादी के पास मुकदमा दायर करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि वे इसके सदस्य नहीं हैं। प्रबंधक निकाय।वादी संख्या 2 से 5 को सोसायटी का सदस्य भी नहीं बताया गया था।याचिकाकर्ताओं के अनुसार, श्री के. एल. मेहता आर्य समाज की मदद से शिक्षा के उद्देश्य को बढ़ावा दे रहे थे, जो फरीदाबाद जिले में जनता के लिए शिक्षा की आवश्यकता को देख सकते थे।28 जनवरी, 1993 को उनका निधन हो गया। प्रबंधक निकाय के सदस्यों के चुनाव के लिए चुनाव सूचना दो स्थानीय समाचार पत्रों में विधिवत प्रकाशित की गई थी।21 फरवरी, 1993 को होने वाले चुनाव की सूचना

सभी वास्तविक जीवन के सदस्यों को 1 फरवरी, 1993 और 2 फरवरी, 1993 को भेजी गई थी। केवल प्रतिवादी संख्या 1 (वादी संख्या 1) को समाज का वास्तविक जीवन सदस्य माना गया था। इस बात से इनकार किया गया कि याचिकाकर्ताओं ने समाज के मामलों का गलत प्रबंधन किया है या शासी निकाय पर स्थायी नियंत्रण रखने का प्रयास किया गया था।इस बात से इनकार किया गया कि वादी चुनाव कार्यक्रम को अमान्य घोषित कराने के हकदार हैं।याचिकाकर्ताओं के अनुसार, 50 व्यक्तियों ने आपत्तियां उठाई थीं और उनकी सदस्यता को अस्वीकार कर दिया गया था क्योंकि उनके दावे झूठे पाए गए थे।दो रसीद पुस्तिकाएँ जारी की गईं।वे लापता थे और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी।रसीद पुस्तिकाओं का गलत सदस्यता बनाने के लिए दुरुपयोग किया गया है।रसीद पुस्तिकाओं के गलत स्थान पर रखने के संबंध में सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी।इसके आधार पर कुछ झूठे सदस्यों को शामिल किया गया है।

(3) अभिलेख पर सामग्री के मूल्यांकन पर ज्ञात विचारण न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला था कि एक प्रथम दृष्टया मामला था जो तैयार किया गया था और सुविधा का संतुलन वादी उत्तरदाताओं के पक्ष में था।विज्ञापन पर अंतरिम रोक लगा दी गई।उसी से आहत होकर एक अपील दायर की गई जिसे खारिज कर दिया गया।प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 8 (संक्षेप में "संहिता") का गैर-अनुपालन एक प्रक्रियात्मक त्रुटि है और यह मामले के गुण-दोष को भौतिक रूप से प्रभावित नहीं करने वाला है। इसलिए, वर्तमान पुनरीक्षण याचिका।

(4) दलीलों के दौरान याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि दीवानी मुकदमा संहिता के आदेश 1 नियम 8 के तहत दायर किया गया है।मुकदमा जारी रहने और अंतरिम निषेधाज्ञा जारी होने के दौरान अदालत से ऐसी कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी।उनके अनुसार, इस तरह की अनुमति के अभाव में, मुकदमा बनाए रखने योग्य नहीं था और इसे खारिज किया जाना चाहिए।उनके तर्क के समर्थन में, इस पर निर्भरता रखी गई थी। जय नारायण और अन्य बनाम चांदगी राम और अन्य के मामले में इस न्यायालय की खंड पीठ का निर्णय[1]इस न्यायालय ने संहिता के आदेश 1 नियम 8 के दायरे पर विचार किया और निष्कर्ष निकाला कि प्रयोज्यता के लिए शर्तें हैं:

(i) पार्टियाँ कई होनी चाहिए;

(ii) पक्षकारों का मुक़दमे में समान हित होना चाहिए;

(iii) न्यायालय की अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए; और

(iv) उन पक्षों को नोटिस दिया जाना चाहिए जिनका वह मुकदमे में प्रतिनिधित्व करने का प्रस्ताव करता है।

(5) यह भी माना गया कि न्यायिक अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है।निर्णय के पैराग्राफ 4 में, डिवीजन बेंच ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकालाः—

> "न्यायिक अनुमति प्राप्त करना उन व्यक्तियों के अलावा अन्य व्यक्तियों को बाध्य करने के लिए एक आवश्यक शर्त है जो वास्तव में मुकदमे के पक्षकार हैं और उनकी गोपनीयता है। यदि यह आवश्यक स्थिति है।पूरा न होने पर मुकदमे को प्रतिनिधि नहीं कहा जा सकता है।मुकदमा दायर करने से पहले अनुमति प्राप्त करना उचित तरीका है।"

(6) सहायक आयुक्त, हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती, सलेम और अन्य बनाम

---

1 1977 पी. एल. जे 527

नट्टमाई के. एस. एलप्पा मुदलियार और अन्य[2] के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश भी संहिता के आदेश 1 नियम 8 के दायरे पर विचार कर रहे थे।यह अभिनिर्धारित किया गया था कि संहिता के आदेश 1 नियम 8 के तहत अनुमति पहले से प्राप्त की जानी चाहिए।निर्णय के पैराग्राफ 9 में, न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:—

> ".....यह केवल उक्त हितकारी सिद्धांत के अनुसार है, आदेश 1 नियम 8 सिविल पी. सी. में प्रक्रिया निर्धारित की गई है।नियम का उद्देश्य अनावश्यक कटौती और मुकदमेबाजी के खर्च से बचना और निर्णय को एक बाध्यकारी बल देना है जिसे अंततः मुकदमे में पारित किया जा सकता है।कोई व्यक्ति आदेश 1 नियम 8 सिविल पी. सी. के तहत प्रक्रिया को अपनाए बिना व्यक्तियों या समुदाय के समूह के दावों को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं कर सकता है, अगर राहत के लिए केवल लोगों के अधिकारों के आधार पर प्रार्थना की जाती है।
>
> इस तरह का समुदाय।इसमें कोई संदेह नहीं है कि आदेश 1 नियम 8, सिविल पी. सी. पूर्व-मानती है कि कई व्यक्तियों में से प्रत्येक को स्वयं मुकदमा करने का अधिकार है।यदि एक व्यक्ति को स्वयं मुकदमा करने का कोई अधिकार नहीं है, तो उसे दूसरों की ओर से मुकदमा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जिनके पास अधिकार है।लेकिन, उन मामलों के बीच अंतर बनाए रखना होगा जहां व्यक्ति एक अधिकार को सामने रखता है जिसे उसने एक समुदाय के सदस्य के रूप में प्राप्त किया है और ऐसे मामले जहां समुदाय के अधिकार को मुकदमे में रखा गया है।यदि यह पहला है, तो व्यक्ति को उसके साथ किए गए गलत के संबंध में अपने अधिकार में मुकदमा चलाने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है, भले ही शिकायत किया गया कार्य समान अधिकार रखने वाले कुछ अन्य व्यक्तियों के लिए भी हानिकारक हो सकता है।यदि यह बाद वाला है, तो आदेश 1, नियम 8, सिविल पी. सी. के तहत प्रक्रिया का पालन करना होगा और ऐसा किए बिना, संबंधित व्यक्ति को कोई राहत नहीं दी जा सकती है।"

(7) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने आर. वेणुगोपाल नायडू और अन्य बनाम वेंकटरायुलु नायडू चैरिटीज और अन्य[3] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया। इसमें संहिता की धारा 92 से निपटने के अलावा, संहिता के आदेश 1 नियम 8 के दायरे पर भी विचार किया गया था।यह अभिनिर्धारित किया गया कि दोनों मुकदमे प्रतिनिधि क्षमता में हैं और सभी इच्छुक व्यक्ति बाध्य हैं।फैसले के पैराग्राफ 10 में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:—

> ".....विद्वान वकील के अनुसार, संहिता की धारा 92 इस अर्थ में एक द्विभाजन सामने लाती है कि "मुकदमे के पक्षकार" और "न्यास में रुचि रखने वाले व्यक्ति" हैं।उनके अनुसार, ट्रस्ट में रुचि रखने वाले व्यक्तियों को मुकदमे का पक्ष माना जा सकता है, हालांकि मुकदमे में निर्णय/डिक्री उन पर बाध्यकारी है।उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 92 के तहत मुकदमा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 8 के तहत दायर मुकदमे से अलग है।हम विद्वान सलाहकार से सहमत नहीं हैं।सिविल पी. सी. की धारा 92 के तहत या सिविल पी. सी. के आदेश 1 नियम-8 के तहत एक मुकदमा बड़ी संख्या में उन व्यक्तियों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है जिनके समान हित होते हैं।एक प्रतिनिधि मुक़दमे की प्रकृति उन सभी को पक्षकार बनाती है जिनका

---

2 ए. आई. आर. 1987 मद्रास 187

3 ए. आई. आर. 1990 एस. सी. 444

मुक़दमे में समान हित है।इसलिए हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वे सभी व्यक्ति जो वेंकटरायुलु नायडू चैरिटी में रुचि रखते हैं, जो निश्चित रूप से एक सार्वजनिक न्यास है, मूल वाद के पक्षकार हैं और इस प्रकार 9 सितंबर, 1910 की योजना-डिक्री के खंड 13 और 14 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं।"

(9) उपरोक्त से यह बहुत स्पष्ट है कि संहिता के आदेश 1 नियम 8 के तहत मुकदमा चलाने से पहले न्यायालय की अनुमति आवश्यक है।हालाँकि, वर्तमान मामले में जो सवाल उठता है वह यह है कि बाद में अनुमति देने का क्या प्रभाव पड़ता है क्योंकि यह विवादित नहीं था कि मुकदमे के लंबित रहने के दौरान अनुमति दी गई है।वास्तव में ऐसा नहीं है।विवाद में कि ऐसी अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए।

(10) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने कुंदन सिंह और अन्य बनाम वर्णम सिंह और अन्य[4] के मामले में इस न्यायालय के फैसले की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया था।इस न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष इस प्रकार हैं:—

> "पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद,मुझे इस अपील में कोई योग्यता नहीं मिलती है। मान लीजिए, विचारण न्यायालय आदेश 1 नियम 8 सी. पी. सी. के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहा। कानून का उक्त प्रावधान प्रकृति में अनिवार्य है।किसी भी सूचना के अभाव में, उप-नियम (2) के प्रावधान निरर्थक हो जाएंगे और इससे गंभीर अन्याय उन व्यक्तियों के खिलाफ डिक्री के रूप में हो सकता है जिन्हें कभी नहीं बताया गया था कि उनके खिलाफ कोई मामला लंबित है।राधा किशन बनाम राजा राम (1976) 78 पुन एल. आर. 271 में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि नोटिस जारी करना केवल एक खाली औपचारिकता नहीं है, बल्कि नियम की प्रयोज्यता के लिए एक अनिवार्य शर्त है। इन परिस्थितियों में, निचली अपीलीय अदालत ने निचली अदालत के आदेश को सही ढंग से दरकिनार कर दिया और आदेश 1, नियम 8 के प्रावधानों का पालन करने के बाद मामले को नए फैसले के लिए भेज दिया।

(11) ओडिशा उच्च न्यायालय द्वारा लखाना नायक और एक अन्य बनाम वासुदेव स्वामी और अन्य [5] के मामले में भी इसी तरह का विचार व्यक्त किया गया था।यह अभिनिर्धारित किया गया कि संहिता के आदेश 1 नियम 8 के तहत अनुमति देने से पहले सभी इच्छुक व्यक्तियों को नोटिस देना आवश्यक है।निर्णय के पैराग्राफ 6 में, न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष इस प्रकार हैं:—

> "इस बात पर किसी भी तरह का विवाद नहीं हो सकता है कि जब सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1, नियम 8 के प्रावधान का आह्वान करते हुए मुकदमा दायर किया जाता है, तो उक्त प्रावधान का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए।अपीलार्थियों के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तर्क को ध्यान में रखते हुए, मैंने निचले न्यायालय के आदेश-पत्र की सावधानीपूर्वक जांच की और विद्वान वकील के विवाद में पर्याप्त बल पाया।आदेश-पत्र के साथ-साथ मामले के अभिलेखों की जांच करने पर, मुझे पता चलता है कि हालांकि 1 अक्टूबर, 1975 के आदेश संख्या 9 द्वारा, न्यायालय ने साप्ताहिक नबीना में नोटिस के प्रकाशन का निर्देश दिया था, लेकिन इसके बाद आदेश-पत्र में या रिकॉर्ड में ऐसी कोई सामग्री नहीं मिली है जिससे यह संकेत मिले

---

4 ए. आई. आर. 1986 पी. एंड एच. 51

5 ए. आई. आर. 1991 उड़ीसा 33

कि ऐसा नोटिस वास्तव में प्रकाशित किया गया था।चूंकि नोटिस बिल्कुल भी प्रकाशित नहीं किया गया है, इसलिए यह पता लगाने के लिए कि क्या आदेश 1, नियम 8, सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान का उचित अनुपालन किया गया है, इस पर विचार नहीं किया जा सकता है।किसी भी सामग्री के अभाव में कि नोटिस विद्वत विचारण न्यायाधीश द्वारा निर्देशित के रूप में प्रकाशित किया गया था, यह अभिनिर्धारित करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है कि आदेश 1 नियम 8, सिविल प्रक्रिया संहिता में निहित प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है और इसके परिणामस्वरूप, मुकदमे के निपटान सहित बाद की कार्यवाही को कानूनी रूप से खराब माना जाना चाहिए।विद्वत विचारण न्यायाधीश के निर्णय को केवल इसी आधार पर अलग रखा जा सकता है।"

(12) हर किशन और अन्य बनाम दुर्गा और अन्य[6] के मामले में दिए गए निर्णय में इस न्यायालय के साथ भी यही दृष्टिकोण प्रचलित था।

(13) इन उदाहरणों के अवलोकन से यह बहुत स्पष्ट है कि वे मूल रूप से इस सवाल से निपटते हैं कि क्या संहिता के आदेश 1 नियम 8 के तहत वैध अनुमति दी गई है या नहीं?यह वर्तमान मामले के तथ्यों में लागू नहीं होगा।जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, तब से मुकदमे के लंबित रहने के दौरान अनुमति प्राप्त की गई है।वर्तमान संशोधन का दायरा उस अनुमति की वैधता में जाना नहीं है।यदि याचिकाकर्ताओं को कोई शिकायत है, तो वे इसकी वैधता को चुनौती दे सकते हैं, जिस पर कानून के अनुसार विचार किया जा सकता है।

(14) इस स्थिति का सामना करते हुए, विद्वान वकील जोर देते हैं, जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है, कि इस तरह से अनुमति दी गई थी

मुक़दमे के लंबित रहने के दौरान अभी भी जन्मे मुक़दमे को मान्य नहीं किया जाएगा।उन्होंने पृथ्वीपाल सिंह बनाम माघ सिंह और अन्य[7] के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया, जिसमें निर्णय के पैराग्राफ 15 में संहिता की धारा 92 पर विचार करते हुए निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गयाः—

> "इस प्रस्ताव के साथ कोई विवाद नहीं है कि अनुमति का अनुदान मुकदमा दायर करने के लिए पूर्ववर्ती शर्त है और यह कि संहिता की धारा 92 के प्रावधान उस संबंध में प्रकृति में अनिवार्य हैं और एक प्रतिवादी उस अधिकार को माफ कर देता है और इस प्रकार एक न्यायालय को अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है।वर्तमान मामले में निचली अदालत का यह कहना निश्चित रूप से सही नहीं था कि छुट्टी देना केवल एक अनियमितता है जिसे ठीक किया जा सकता है या यह माना जाना चाहिए कि प्रतिवादी ने लिखित बयान दायर किया है और उसने मुकदमा दायर करने पर सवाल उठाने के अधिकार को माफ कर दिया है।"

(15) हाल ही में के मामले में, ठाकरदवारा, पटियाला व अन्य बनाम नागर सिंह और अन्य[8], संहिता की धारा 92 पर विचार करते समय इसी तरह का तर्क प्रबल हुआ और इसका समर्थन किया गया।यह अभिनिर्धारित किया गया था कि वैध अनुमति एक पूर्व शर्त है और कोई भी मृत जन्म वाले सूट में जीवन नहीं डाल सकता है।जो निष्कर्ष सामने आए हैं वे इस प्रकार हैंः—

---

6 1996(1)PLR 787
7 AIR 1982 P&H 137
8 1998(3)PLR 81

"कोई भी मृत जन्म वाले सूट में जीवन नहीं डाल सकता है।एक बार मुकदमा दायर करने से पहले अनुमति लेनी पड़ती थी।उस स्थिति में यह निष्कर्ष निकालने के अलावा कोई बचाव नहीं था कि एक बार अनुमति दिए जाने के बाद, यह प्रतिवादीगण को केवल एक नया मुकदमा दायर करने की अनुमति देगा, यदि आवश्यकता हो तो पुरानी अनुमति के साथ जारी रखने के बजाय उक्त अनुमति के आधार पर।यह सच है कि किंटाली चीन जगन्धाम और अन्य (उपरोक्त) के मामले में उड़ीसा उच्च न्यायालय ने कहा था कि एक बार अनुमति दिए जाने के बाद, उस स्थिति में, भले ही यह मुकदमे के लंबित रहने के दौरान दी गई हो, यह माना जाना चाहिए कि मुकदमा उस तारीख से दायर किया गया था जब अनुमति दी गई थी।यह माना गया थाः—

> "इसलिए, मेरा मानना है कि धारा 92 के तहत छुट्टी एक अनिवार्य शर्त है।वादी-याचिकाकर्ताओं के लिए एक याचिका दायर करने की उचित प्रक्रिया है। अनुमति के लिए आवेदन और उसके साथ उनके द्वारा दायर किए जाने वाले प्रस्तावित मुकदमे के मसौदा वाद की एक प्रति जोड़ना ताकि अदालत को अनुमति देने में सक्षम बनाया जा सके, क्योंकि अनुमति का सख्ती से अर्थ लगाया जाना है। स्थापित मुकदमा काफी हद तक दी गई अनुमति के अनुसार होना चाहिए।चूँकि अनुमति देना पूर्ववर्ती शर्त है, इसलिए अनुमति देने से पहले वैध रूप से मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है।आम तौर पर, अनुमति दिए बिना धारा 92 के दायरे में आने वाली राहत या राहत की मांग करने वाली शिकायत को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।लेकिन, जहां कोई मुकदमा दर्ज किया गया है या अनुमति देने से पहले अंतरिम आदेश पारित किए गए हैं, तो उसे अक्षम, अमान्य और ईमानदार माना जाएगा।जहां किसी लंबित मुकदमे में अनुमति दी जाती है, वादी या तो दी गई अनुमति के अनुरूप उसी के प्रतिनिधित्व के लिए शिकायत को वापस करने के लिए कह सकता है, या अदालत से अनुमति दिए जाने की तारीख को और उसके बाद से शुरू की गई शिकायत पर विचार करने के लिए कह सकता है, यदि शिकायत काफी हद तक अनुमति के अनुरूप है।"

> "इस संबंध में किसी को इस विचार को स्वीकार करना मुश्किल लगता है कि एक बार मुकदमे के लंबित रहने के दौरान अनुमति दिए जाने के बाद, अनुमति की तारीख से मुकदमा पंजीकृत माना जाए।लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उड़ीसा उच्च न्यायालय को इस तरह का विचार रखने के लिए जो प्रेरित किया वह यह था कि अनुमति देने से पहले अंतरिम आदेश पारित किया गया था।सीपोर्ट बहुत चिंतित था कि यह अक्षम और अमान्य हो जाएगा।वर्तमान मामले में ऐसा नहीं है।अनुमति मुकदमे के लंबित रहने के दौरान प्राप्त की गई थी और उक्त अनुमति के आधार पर, यदि ऐसा सलाह दी जाती है तो प्रतिवादीगण केवल एक नया मुकदमा ला सकते हैं।वे उस मुकदमे को जारी नहीं रख सकते जो अनुमति के बिना बनाए रखने योग्य नहीं था।सी. पी. सी. की धारा 92 की उप-धारा (1) और (2) के प्रावधान हैंः

अनिवार्य है।"

(16) क्या संहिता के आदेश 1 नियम 8 में संहिता की धारा 92 के उक्त तर्क को लागू किया जा सकता है?जवाब नकारात्मक होना चाहिए।इस विशेष विवाद को समझने के लिए, संहिता की धारा 92 की उप-धारा (1) के प्रासंगिक भाग का संदर्भ दिया जा सकता है जो निम्नानुसार हैः—

> "92. सार्वजनिक दानः**—(1)** धर्मार्थ या धार्मिक प्रकृति के सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए बनाए गए किसी स्पष्ट या रचनात्मक न्यास के किसी कथित उल्लंघन के मामले में, या जहां प्रशासन या ऐसे किसी न्यास के लिए न्यायालय का निर्देश आवश्यक समझा जाता है, महाधिवक्ता, या न्यास में रुचि रखने वाले दो या दो से अधिक व्यक्ति और [न्यायालय की अनुमति] प्राप्त करने के बाद, मूल अधिकार क्षेत्र के प्रमुख सिविल न्यायालय में या राज्य सरकार द्वारा उस ओर से सशक्त किसी अन्य न्यायालय में, जिसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर न्यास का पूरा या विषय-वस्तु का कोई भी हिस्सा एक डिक्री प्राप्त करने के लिए स्थित है, एक मुकदमा दायर कर सकता है, चाहे वह विवादास्पद हो या नहीं।

(17) जिस संहिता के साथ हम वर्तमान में काम कर रहे हैं, उसके आदेश 1 नियम 8 का भी उल्लेख किया जा सकता है।यह नीचे लिखा हैः—

> **"8.** एक व्यक्ति समान हित में सभी की ओर से मुकदमा कर सकता है या बचाव कर सकता है।—(1) जहाँ एक ही सूट में समान रुचि रखने वाले कई व्यक्ति हैं -
>
> (a) -ऐसे व्यक्तियों में से एक या अधिक व्यक्ति, न्यायालय की अनुमति से, मुकदमा कर सकते हैं या उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है, या इस तरह के इच्छुक सभी व्यक्तियों की ओर से या उनके लाभ के लिए ऐसे मुकदमों का बचाव कर सकते हैंः
>
> (b) न्यायालय निर्देश दे सकता है कि ऐसे व्यक्तियों में से एक या अधिक मुकदमा कर सकते हैं या मुकदमा किया जा सकता है या मुकदमे का बचाव कर सकते हैं, सभी व्यक्तियों की ओर से, या उनके लाभ के लिए।"

(18) सी. एल. सी. ओ. एन. क्लोजी स्क्रूटनी पर, एक स्पष्ट अंतर है डबल्यू. ओ. संहिता की धारा 92 के तहत, विधानमंडल इन शब्दों का उपयोग करता है "और न्यायालय की अनुमति प्राप्त करने के बाद एक मुकदमा दायर कर सकता है।"यह स्पष्ट है कि यह मुकदमे की स्थापना से पहले एक अनिवार्य शर्त है।इस तरह की अनुमति के बिना मुकदमा आगे नहीं बढ़ सकता है।जबकि संहिता के आदेश 1 नियम 8 के तहत, विधानमंडल ने "न्यायालय की अनुमति से" अभिव्यक्ति का उपयोग किया है।यद्यपि मुकदमा दायर करने से पहले न्यायालय की अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए,

फिर भी इसे स्थगित किया जा सकता है और बाद में मुकदमे के लंबित रहने के दौरान दिया जा सकता है, जैसा कि इसके बाद देखा गया है।भाषा में स्पष्ट अंतर है-।संहिता की धारा 92 के तहत, कोई भी कदम उठाने से पहले न्यायालय की आवश्यक अनुमति आवश्यक है।संहिता के आदेश 1 नियम 8 के तहत दायर मुकदमे में ऐसा नहीं होगा।इस संबंध में शांतिलाल बर्दीचंद महाजन बनाम चंपालाल राधाजी और अन्य (8) के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है।इसमें, एक मुकदमा दायर किया गया था और विशेष रूप से शिकायत में यह उल्लेख किया गया था कि यह संहिता के आदेश 1 नियम 8 के तहत अन्य लेनदारों की ओर से जारी नहीं किया गया था।न्यायालय सहित प्रत्येक संबंधित निकाय ने इसके बारे में जानकारी ली।पहली बार *
अपील में यह बात सामने आई।यह अभिनिर्धारित किया गया था कि ऐसी अनुमति अपील में दी जा सकती है।फैसले के पैराग्राफ 10 में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने निम्नलिखित निर्णय दिया:—

" वर्तमान मामले में, शिकायत काफी स्पष्ट है और वादी की स्थिति वास्तव में अधिक मजबूत है।मुकरेमदा बनाम छगन ए. आई. आर. *1956* बम 491 में दर्ज मामले में, तत्काल मामले की तरह, प्रतिनिधि क्षमता में एक के रूप में शिकायत दायर की गई थी।आदेश में कोई औपचारिक अनुमति दर्ज नहीं की गई थी लेकिन कुछ नोटिस जारी किए गए थे।इसलिए अदालत ने माना कि अनुमति देने वाले औपचारिक आदेश की अनुपस्थिति वास्तव में महत्वहीन थी; लेकिन हुबली पंजारापोल बनाम में रिपोर्ट किए गए पहले के बॉम्बे मामले में।सरस्वताव बायप्पा, ए. आई. आर. 1953 बम 334, नोटिस जारी करने में एक वास्तविक चूक थी और यह माना गया था कि मुकदमे के लंबित रहने के दौरान ही अनुमति ली जा सकती है और नोटिस जारी किए जा सकते हैं।इस प्रकार, अधिकार इस दृष्टिकोण के लिए पर्याप्त है कि छूट को अपीलीय स्तर पर भी ठीक किया जा सकता है, यदि मुकदमे की प्रकृति में बदलाव नहीं किया जाता है।"

(19) कुथुकुट्टी कुनहॉल के मामले में केरल उच्च न्यायालय पुत्र कुन्हलवी मुसलियार और अन्य बनाम पक्कथ एनू के पुत्र अब्दुल्ला और।अन्य[9] ने इसी तरह की स्थिति से निपटा और निर्णय के पैराग्राफ 9 में निष्कर्ष निकाला:—

> ".....अदालत ने मार्च, 1956 में एक स्थानीय समाचार पत्र में नोटिस के प्रकाशन का आदेश दिया, यानी मुकदमा दायर होने और स्थानीय समाचार पत्र में नोटिस प्रकाशित होने के तुरंत बाद।यह देखा गया है कि जिस तारीख को फैसला सुनाया गया था, उस तारीख को अदालत ने एक आदेश पारित किया था जिसमें वादी को प्रतिनिधि क्षमता में मुकदमा करने की अनुमति दी गई थी और प्रतिवादियों को प्रतिनिधि क्षमता में मुकदमे का बचाव करने की अनुमति दी गई थी।उन तथ्यों के आधार पर अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि प्रावधानों या आदेश 1, नियम 8 का पालन नहीं किया गया है।उनका तर्क था कि अनुमति का आदेश अमान्य था क्योंकि इसे पत्र में सूचना के प्रकाशन के बाद पारित किया गया था।"

---

9 ए. आई. आर. 1965 केरल 200

(20) हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने श्रीमती. राम प्यारी बनाम श्री अमर सिंह और अन्य [10] कुछ इसी तरह की स्थिति से निपट रहे थे।संहिता के आदेश 1 नियम 8 के तहत शिकायत के साथ एक आवेदन दायर किया गया था।यह अभिनिर्धारित किया गया कि इसका निपटारा करना न्यायालय का कर्तव्य है।लेकिन छुट्टी बाद में दी जा सकती है।दर्ज किए गए सटीक निष्कर्ष इस प्रकार हैं:—

> ".....इस मामले के तथ्यों पर, ऐसा लगता है कि यह कहना जल्दबाजी होगी कि यह शर्त पूरी हो गई है।प्रावधान यह विचार करता है कि मुकदमा विफल होना चाहिए, और मेरी राय है कि जब तक आदेश 1, नियम 8 के तहत आवेदन लंबित है, तब तक मुकदमे के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है।आवेदन वादी के साथ दायर किया गया था, और इसका निपटारा करना न्यायालय का कर्तव्य है।ऐसा करने में चूक को मुकदमे की सुनवाई के दौरान किसी भी स्तर पर दूर किया जा सकता है। आम तौर पर, आदेश 1 नियम 8 के तहत अनुमति मांगी जानी चाहिए और जब मुकदमा दायर किया जाता है तो इसके अनुदान पर विचार किया जाना चाहिए। लेकिन मुकदमे की शुरुआत में अनुमति प्राप्त करने में चूक मुकदमे को खारिज करने के कारण के रूप में काम नहीं कर सकती है।अधिकार क्षेत्र का कोई सवाल शामिल नहीं है।मुकदमा दायर होने के बाद किसी भी स्तर पर अनुमति दी जा सकती है।

(21) हाल ही में, एन. आनंदन बनाम अयन्ना गौंडर और अन्य[11] के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने इसी तरह की स्थिति से निपटने के लिए एक ही दृष्टिकोण अपनाया और निष्कर्ष निकाला कि

> ".....आदेश 1 नियम 8 (एल) (ए) में उपयोग की जाने वाली भाषा इस प्रकार है
>
> > "ऐसे व्यक्तियों में से एक या अधिक व्यक्ति, न्यायालय की अनुमति से, मुकदमा कर सकते हैं "यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए।
> > कि आदेश 1 नियम 8, सी. पी. सी. में कही गई अनुमति को पूर्ववर्ती शर्त नहीं माना गया है, जैसा कि धारा 92, सी. पी. सी. के तहत अनुमति के मामले में किया गया है। आदेश 1, नियम 8, सी. पी. सी. के तहत अनुमति, मुकदमे की स्थापना के बाद भी और यहां तक कि एक संशोधन की अनुमति देकर अपीलीय चरण में भी दी जा सकती है, यदि ऐसा संशोधन मुकदमे की प्रकृति को भौतिक रूप से नहीं बदलता है (ए. आई. आर. *1947* एम. डी. 205, मूका पिल्लई बनाम वलवंदा पिल्लई और ए. आई. आर. 1943 एम. डी. 161, मुथुकरुप्पा एथांडर बनाम अप्पावु नादर)।

---

10 ए. आई. आर. 1978 एच. पी. 22

11 AIR 1994 Madras 43

(22) जैसा कि ऊपर देखा गया है, संहिता के आदेश 1 नियम 8 और धारा 92 में उपयोग की गई साधारण भाषा से स्पष्ट है कि संहिता का आदेश 1 नियम 8, न्यायालय की अनुमति बाद में प्राप्त की जा सकती है।

(23) इस मामले के विशिष्ट तथ्यों में इस संबंध में एक महत्वपूर्ण कारण है।संहिता के आदेश 1 नियम 8 के तहत आवेदन शिकायत के साथ दायर किया गया था।विद्वत विचारण न्यायालय ने उस समय कोई अनुमति नहीं दी थी।वास्तव में, किसी को भी न्यायालय की गलती का नुकसान नहीं उठाना है या लाभ नहीं उठाना है।जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इस तरह की अनुमति पर विचार किया जाना चाहिए और प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए।एक बार जब इस तरह के आवेदन को मुकदमे के साथ जोड़ा जाता है, तो वादी को इस संबंध में परेशान नहीं किया जा सकता है।अब दी गई अनुमति मुकदमे को अमान्य नहीं करेगी।इसलिए, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि वाद के लंबित रहने के दौरान इस प्रकार दी गई अनुमति से वाद को खारिज करने से बचा जा सकता है।

(24) मामले के गुण-दोष के संबंध में, विद्वत विचारण न्यायालय और विद्वत अतिरिक्त जिला न्यायाधीश दोनों ने पाया था कि वादी के पक्ष में कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं है।यह नोट किया गया है।कि एमटीएस। विमल मेहता और श्री बी. एल. भाटिया को संस्थापक सदस्यों के रूप में दिखाया गया है।उन्हें प्रथम दृष्टया ऐसा नहीं दिखाया गया था।वास्तव में, यह स्वीकार किया गया था कि प्रतिवादी संख्या 4 श्री बी. एल. भाटिया को अनजाने में संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।इसके अलावा, रसीद पुस्तिकाओं से यह नोट किया गया है कि सूची में उल्लिखित सदस्यों ने अपनी सदस्यता का भुगतान किया है, हालांकि उन्हें सदस्यों की अंतिम सूची में शामिल नहीं किया गया था, जबकि कुछ अन्य व्यक्तियों को अमान्य रूप से सदस्यों के रूप में शामिल किया गया है।इस संबंध में आगे की चर्चा केवल किसी भी पक्ष को शर्मिंदा करेगी।कहने के लिए पर्याप्त है, प्रथम दृष्टया वादी-प्रत्यर्थियों के पक्ष में मामला तैयार किया गया था।यदि याचिकाकर्ताओं की योजना के अनुसार चुनाव आयोजित किए जाते हैं तो सुविधा का संतुलन भी वादी-प्रत्यर्थियों के पक्ष में होगा।यह वादी उत्तरदाता हैं जिन्हें अपूरणीय क्षति होगी।इस प्रकार विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।

(25) इन कारणों से, पुनरीक्षण याचिका विफल होनी चाहिए और खारिज कर दी जाती है।हालाँकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ कुछ भी नहीं कहा गया है जो मामले के गुण-दोष पर राय व्यक्त करता है।याचिकाकर्ताओं को संहिता के आदेश 1 नियम 8 के तहत दी गई अनुमति को चुनौती देने की स्वतंत्रता और इस संबंध में कोई राय व्यक्त नहीं की गई है।निचली अदालत को पहले से पारित आदेश के संदर्भ में मुकदमे में तेजी लाने और उसे पूरा करने का निर्देश दिया जाता है।

एस०सी०के०

अस्वीकरण : *स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा*

में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वियन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

डा० सुशीला
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
रोहतक,हरियाणा